2 खनिज विभाग की अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही

3 रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का आगाज

5 प्रखर वक्ता और कुशल विदेश मंत्री के रूप में विशिष्ट स्थान

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 18 प्रति सोमवार, 9 सितंबर 2024 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

आखिर कब बंद होगा भ्रष्टाचार का यह नया तंत्र

शिवराज के समय शुरू हुआ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति का कल्चर मोहन सरकार में भी है बरकरार

आखिर कब तक युवा बेरोजगारी की ठोकर खायेंगे और रिटायर्ड कर्मचारी मलाईदार पोस्ट पर बैठकर भ्रष्टाचार करेंगे

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में इन दिनों रिटायर्ड कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति का एक नया कल्चर विकसित हो गया है। यह कल्चर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से शुरू हुआ था जो अभी तक स्थायी तौर पर चल रहा है। खास बात यह है कि इस कल्चर के लागू होने से एक ओर जहां युवा और प्रतिभावान लोग रोजगार से वंचित हो रहे हैं। वहीं दूसरी राज्य में बेरोजगारी दर निरंतर बढ़ती जा रही है। यही नहीं सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति किये जाने से शासन पर आर्थिक रूप से भी अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस बात की ओर

सख्त तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे इस तरह से नियुक्ति किये जाने और भ्रष्टाचार के इस तंत्र को मजबूती देने का यह जो सिलसिला प्रदेश में चल रहा है उसे खत्म किया जाये और नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाये।

बीडीए में कई बाबू दोबारा आकर बैठ गये

ताजा मामला भोपाल विकास प्राधिकरण का है जहां एक नहीं कई रिटायर्ड कर्मचारी बाबू वापस आकर टेबल कुर्सी लगाकर काम करने लगे हैं और प्राधिकरण के मुखिया को इस बात की भनक तक नहीं है। पिछले दिनों बीडीए के एक बाबू द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने का मामला सामने आया तब बीडीए में चल रहे रिटायर्ड कर्मचारियों के इस गौरखधंधे से पर्दाफाश हुआ। (शेष पेज 7 पर)

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लिये गये ऐतिहासिक फैसले से महिलाओं के जीवन में आया बदलाव

महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से बनाया संबल

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार की प्राथमिकताओं में किसान, महिला, युवा, बेटी शामिल हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए निरंतर नये-नये नवाचार करते हुए योजनाओं का निर्माण कर रही है। इन योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि आज राज्य में महिलाएं खुशहाल हैं। महिलाओं

के जीवन को सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 'महतारी वंदन योजना' को मंजूरी देने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना को लागू करने का वादा किया था जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। (शेष पेज 7 पर)

इतिहास गवाह है, जंग में जोश से ज्यादा संगठनात्मक अनुभवी अधिनायक युद्ध जितवाते हैं

अनुभवहीन नेताओं के हाथों में कमान, पार्टी का भविष्य संकट में डाल रहा आलाकमान

आखिर नर्सिंग घोटाले को कांग्रेस ने क्यों दबा दिया, जबकि 2028 में मध्यप्रदेश सरकार की चाबी है नर्सिंग घोटाला

-विजया पाठक

आज से कोई 4 साल बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं, पर प्रदेश में कांग्रेस की हालत अभी से पतली नजर आ रही है। इसका एक सीधा-सीधा कारण है तजुर्बेकार कांग्रेसी नेताओं की कमी होना। ऐसे अनुभवी और प्रभावी नेता जो संगठन को बुन सकें, पार्टी को खड़ा कर सकें। मुझे अच्छे से याद है कांग्रेस का संगठन 2013 के चुनाव के बाद ऐसे ही निर्जीव हो गया था, उस समय सरकार के मुखिया शिवराज के

मध्यप्रदेश कांग्रेस में संगठन को खड़ा करने के लिए कमलनाथ जैसे अनुभवी नेताओं की है नितांत आवश्यकता

खिलाफ व्यापमं जैसा बड़ा मुद्दा होने के बावजूद पार्टी माहौल नहीं खड़ा कर पा रही थी। इसी बीच आलाकमान ने कमलनाथ को प्रदेश का सरदार बना दिया और बस अपने अनुभवी संगठात्मक कौशल के दम पर अप्रासंगिक लगने वाले मुद्दे असरदार लगने लगे। (शेष पेज 2 पर)

आखिर नर्सिंग घोटाले को कांग्रेस ने क्यों दबा दिया, जबकि 2028 में मध्यप्रदेश सरकार की चाबी है नर्सिंग घोटाला

(पेज 1 का शेष)

अनुभव का एक उदाहरण मराठा और मुगल युद्ध था, जैसे औरंगजेब के पास मराठा फौज से कई गुना शक्तिशाली फौज थी पर मराठा सरदारों के अनुभव ने उस शक्तिशाली फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज भी वही दौर कांग्रेस का लौट आया है। जहां उनके युवा नेता प्रदर्शन तो कर रहे हैं, पर अपनी अनुभवहीनता के कारण सरकार का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है जिस जोश के साथ इन्होंने नर्सिंग घोटाला विधानसभा से सड़क तक उठाया, अब उसमें खामोशी से दबा दिया गया है। क्या परदे के पीछे नर्सिंग घोटाले के दागी मंत्री के साथ कोई डील हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के पदों में बैठे नेता के काफी लोग मंत्री के भी हितैषी हैं। खैर समय अब आ गया है जब आलाकमान मध्य प्रदेश के बारे में सोचे। यह सोचे कि क्या कारण है कि जब कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश की सीटें लगभग 50000 वोटों के ऊपर से ही हारी। पार्टी को तुरंत रणनीतिक, संगठन को खड़ा करने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी नेता चाहिए। वैसे भी काठ की हांडी जैसी लाडली बहना योजना बार-बार नहीं चढ़ती।

मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों संगाठनात्मक नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी इच्छानुसार लोगों की नियुक्तियां करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान प्रदेश में उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्तियों को लेकर आवश्यकता से अधिक पटवारी पर भरोसा जता रहा है। पटवारी और आलाकमान के आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में मनभेद की स्थिति बनती दिख रही है। अगर समय रहते पार्टी आलाकमान ने नेताओं के बीच पनप रहे इस मनभेद को समाप्त नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश कांग्रेस का अस्तित्व प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो जायेगा। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस आलाकमान इन सभी संगठात्मक नियुक्तियों में एक बार फिर युवाओं पर भरोसा जताने जा रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो युवा कंधों पर संगठन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर एक बार फिर आलाकमान गलत फैसला लेने जा रहा है। पहले ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अनुभवहीन नेताओं को कमान सौंपकर पार्टी का अस्तित्व खतरे में डाल चुकी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज अब एक फिर ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं यह एक बड़ा चिंता का विषय है।

सिर्फ आंदोलन करने से नेता नहीं बनते

पार्टी आलाकमान को यह बात समझना होगा कि हर लड़ाई आंदोलन नामक हथियार से नहीं जीती जाती। आलाकमान ने जिन आंदोलन करने वाले नेताओं पर भरोसा जताते हुए प्रदेश की कमान उनके हाथ में सौंपी है वही नेता अब पार्टी की प्रदेश में लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। किसी ने सही कहा है कि हर लड़ाई को हथियार से नहीं जीता जाता है कुछ लड़ाईयां ऐसी भी होती हैं जहां आपको अनुभव की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को अगर हम देखें तो सभी अनुभवहीन नजर आते हैं। जो सिर्फ आंदोलन, धरना प्रदर्शन को ही राजनीति करना समझते हैं और पिछले छह महीने से यही करते नजर आ रहे है। यही कारण है कि प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता अब ना के बराबर समझ आ रही है। ऐसे नेता आंदोलन करते हैं और मौका देखकर हाथ मिला लेते हैं।

अनुभवी राजनेताओं को करना होगा एकजुट

पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मध्यप्रदेश के सियासी बिसात को बेहतर ढंग से समझकर नये सिरे से अपने नेताओं का चयन करना होगा। इसमें एक तरफ जहां युवाओं की टीम हो वहीं, दूसरी तरफ अनुभवी राजनेताओं की। क्योंकि अनुभवी राजनेताओं के होने का ही कारण है कि कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया। लेकिन कपिल सिब्बल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रणव मुखर्जी, मनीष तिवारी ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें किनारे कर पार्टी रसातल में जाती हुई प्रतीत हो रही है। इसका परिणाम हम सभी के सामने हैं कि मध्यप्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। इसके अलावा दिल्ली में भी पार्टी लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। इन सभी अनुभवों पर दोबारा से मंथन करके आलाकमान को निर्णय लेने की आवश्यकता है। प्रदेश में गठित हुए नर्सिंग घोटाला कांग्रेस के लिए सत्ता सीढ़ी जैसा था, पर शायद इस मुद्दे को प्रदेश आलाकमान ने बेच डाला।

सूत्रों के मुताबिक मंत्री विश्वास सारंग को अभयदान के पीछे क्या हुआ है बड़ा सौदा

अनुभवहीन होने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रदेश भाजपा के मंत्री विश्वास सारंग द्वारा किये गये नर्सिंग घोटाले में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी कुछ खास विरोध नहीं कर पाई। बल्कि अगर यही कोई अनुभवी नेता होते तो वे योजनाबद्ध ढंग से इस पूरे मसले को विधानसभा पटल पर लाते और आरोपी मंत्री को पद से इस्तीफा दिलवाकर ही दम लेते। लेकिन न जाने अचानक बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे पटवारी एकदम नर्सिंग घोटाले पर चर्चा करना ही बंद कर दिये।

कांग्रेस का गुटबाजी से रहा है गहरा नाता, प्रदेश कांग्रेस ने 2024 लोकसभा में छिंदवाड़ा में दिया था भाजपा का साथ

मध्य प्रदेश में कांग्रेस और गुटबाजी का गहरा नाता हो चला है। दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। लोकसभा में एकमात्र जीत प्राप्त करने योग्य छिंदवाड़ा सीट को प्रदेश कांग्रेस ने हरवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पर प्रदेश कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में भाजपा के लिए काम किया और कांग्रेस को ही हरवा दिया गया था। यह बात चुनाव में होने वाले टिकट वितरण से लेकर जिम्मेदारियां

सौंपे जाने तक में नजर आती है। इसका ताजा उदाहरण प्रदेश कार्यकारिणी है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले जीतू पटवारी को लगभग 8 माह हो गए हैं, मगर अब तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। राज्य में किसी दौर में कांग्रेस सत्ता में थी, संगठन भी मजबूत हुआ करता था, मगर वर्ष 2003 के बाद ऐसी स्थितियां बनी कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई।

2023 में कांग्रेस पार्टी नहीं हारी थी, बल्कि लाडली बहना योजना जीती थी

पार्टी विधानसभा के लगातार तीन चुनाव हार गई। लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अन्य दलों के सहयोग से सत्ता हासिल की। पार्टी को सत्ता जरूर मिल गई, मगर गुटबाजी के रोग ने उसे ज्यादा दिन सत्ता हाथ में नहीं रहने दिया। 15 महीने ही कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने काम किया। 2028 का चुनाव कांग्रेस जीत सकती है बशर्ते उनके पास अनुभवी सरदार हो जैसे मराठा-औरंगजेब के युद्ध के समय मराठा फौज के पास थे। (शेष पेज 3 पर)

कलेक्टर के दिशा निर्देशन मे खनिज विभाग की अवैध उत्खनन के विरुद्ध कार्यवाही जारी

17 ट्रैक्टर-ट्राली वाहन एवं एक मिनी ट्रक किया जब्त

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। कलेक्टर सोनिया मीना के दिशा निर्देशन में एवं जिला खनिज अधिकारी दिवेश मरकाम के मार्ग दर्शन में खनिज विभाग की टीम के द्वारा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी है। बताया जा रहा कि खनिज विभाग द्वारा अलग अलग तिथियों पर कार्यवाही करते हुए रेत खनिज का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने पर 17 ट्रैक्टर- ट्राली एवं 1 मिनी ट्रक इस प्रकार कुल 18 वाहनों को जब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा 1 अगस्त को ग्राम खापरखेड़ा तहसील पिपरिया में रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 1 ट्रैक्टर ट्राली वाहन जब्त कर पुलिस थाना मंगलवारा पिपरिया की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। इसी प्रकार 10 अगस्त को ग्राम रैसलपुर तह. इटारसी में 2 वाहन ट्रेक्टर ट्राली, ग्राम चपलासर तह. माखननगर में रेत का भण्डारण में लिप्त पाये जाने पर 1 मिनी ट्रक, 11 अगस्त को ग्रीन पार्क ढाबा के पास नर्मदापुरम में रेत का अवैध परिवहन करने पर 1 वाहन ट्रैक्टर ट्राली, 14 अगस्त को ग्राम रैसलपुर तह. इटारसी एवं मालाखेड़ी तह.नर्मदापुरम से रेत खनिज का अवैध परिवहन करने पर 2 वाहन ट्रैक्टर ट्राली, 18 अगस्त को ग्राम रेसलपुर तहसील इटारसी में रेत खनिज का अवैध परिवहन करने पर 5 ट्रालियां, 27 अगस्त को बंजारा कॉलोनी मालाखेड़ी रोड नर्मदापुरम में रेत खनिज का अवैध परिवहन करने पर 1 वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली

को जप्त कर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परिसर नर्मदापुरम की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़े किए गए हैं।इसके अतिरिक्त राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा 25 अगस्त को मालाखेड़ी रोड नर्मदापुरम पर रेत खनिज का अवैध परिवहन करने पर 1 वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर पुलिस थाना देहात नर्मदापुरम में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। 28 अगस्त को गुर्रा रेलवे फाटक के पास तहसील इटारसी में रेत खनिज का अवैध परिवहन करने पर 01 वाहन ट्रैक्टर ट्राली एवं रामपुर गुर्रा रोड से तथा कांदई रोड पर रेत का अवैध भंडारण करने पर 02 वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर रामपुर थाना की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। 29 अगस्त को अमृत केयर हॉस्पिटल नर्मदापुरम के पास रेत का अवैध परिवहन करने पर 01 वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर पुलिस थाना देहात नर्मदापुरम में खड़ा किया गया। उक्त जब्त वाहनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण निवारण नियम 2022 के तहत कार्यवाही कर 6 लाख 11 हजार 250 रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है।

(जगत फीचर्स)

रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का आगाज, मांदर की थाप पर जमकर थिरके मुख्यमंत्री

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रदेश की सबसे खास और चर्चित कार्यक्रम चक्रधर समारोह का 7 सितंबर से शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह का शुभारंभ किया। चक्रधर समारोह के पहले दिन पद्मश्री से सम्मानित हेमा मालिनी ने राधा रास बिहारी नृत्य नाटिका पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। बता दें कला और संगीत की नगरी के रुप में जाने जाने वाले रायगढ़ में दस दिनों तक 39वां चक्रधर समारोह चलेगा। 10 दिनों तक चलने वाले समारोह में देश के कोने-कोने से कलाकार शामिल होने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "गीत और संगीत के क्षेत्र में रायगढ़ और संगीत सम्राट महाराज चक्रधर का खास स्थान है। संगीत सम्राट महाराज चक्रधर जी ने शास्त्रीय संगीत कला को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया, एक नई पहचान दी, संगीत की विरासत को विशाल और समृद्ध बनाया। इस समारोह में सीएम विष्णुदेव साय अलग अंदाज में नजर आए। यहां उन्होंने अपने गृह ग्राम बगिया के कर्मा नर्तकों को मांदर की थाप पर कर्मा नृत्य करते देख खुद को नहीं रोक नहीं पाए और मंच पर ढोलक बजाकर कर्मा नृत्य किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और ओपी चौधरी ने भी कर्मा नृत्य किया। चक्रधर समारोह के मंच से रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संगीत महाविद्यालय की मांग मंच से ही सीएम से कर दी। इसके बाद सीएम साय ने मंच से ही रायगढ़ में संगीत महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही सीएम साय ने प्रदेश वासियों को गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में बदल गई है छत्तीसगढ़ की स्थिति- हेमा मालिनी

मथुरा की सांसद प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं नृत्यांगना पद्मश्री हेमा मालिनी ने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नंबर वन राज्य बने छत्तीसगढ़। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ साय के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगा। हेमामालिनी ने कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं होगी कभी फण्ड की कमी। उन्होंने कहा साय के नेतृत्व में आदिवासियों, किसानों और महिलाओं की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। उन्होंने कहा पहले नक्सल समस्या के कारण लोग यहां आने में हिचकिचाते थे लेकिन अब साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की स्थिति बदल गई है।

आखिर नर्सिंग घोटाले को कांग्रेस ने क्यों दबा दिया

(पेज 2 का शेष)

पार्टी ने दिसंबर 2023 विधानसभा में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी को सौंपी। जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जहां कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद पहली बार एक भी सीट नहीं ला पाई।

पार्टी की गुटबाजी कार्यकारिणी गठन में बाधक

नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी का इंतजार है, मगर कांग्रेस का फिर वही गुटबाजी का रोग नई कार्यकारिणी के गठन में बाधक बना हुआ है। मीडिया विभाग के अलावा कुछ नेताओं के पास जिम्मेदारी है, मगर ज्यादातर पद अब भी खाली हैं और दावेदार जोर आजमाइश कर रहे हैं, साथ में जिम्मेदारी का इंतजार भी। पार्टी लगातार सत्ता के खिलाफ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रही है, मगर वैसी ताकत दिखाने में असफल है जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करते हैं।

बिना पद के नेताओं की सक्रियता में कमी

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए आता है और यह तभी संभव है जब उसे कोई पद हासिल हो। संबंधित नेता के पास अगर कोई पद नहीं है तो वह न तो सक्रिय रहता है और न ही कार्यकर्ताओं के बीच उसकी पकड़ होती है। इसका असर पार्टी की गतिविधियों पर पड़ता है और राज्य में यही हो रहा है। यह बात अलग है कि कई बड़े नेता या तो आज सक्रिय नहीं हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। उसके बावजूद अंदर खाने की खींचतान कम नहीं हो रही है। उसी का नतीजा है कि आज जीतू पटवारी में इतनी योग्यता नहीं है कि वह अपनी टीम को बना सकें।

उज्जैन और छतरपुर मामले पर कमलनाथ ने जताई चिंता, सरकार को कठघरे में खड़ा किया

उज्जैन और छतरपुर के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। कमलनाथ ने कहा यह तो एक उज्जैन का मामला है पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो चुकी है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। कमलनाथ ने कहा कि लूट और रेप के मामले पूरे प्रदेश में हर जगह से सामने आ रहे हैं। यह घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं।

छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग में ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत, सरकारी प्रक्रियाओं में होगी पारदर्शिता और सुधार

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली के तहत, वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया। वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग के मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर विभाग में ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। इस सॉफ्टवेयर आधारित ऑनलाइन प्रणाली के तहत, मंत्रालय की सभी फाइलें अब ई-ऑफिस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी।ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में सुधार होगा। इस प्रणाली के जरिए लंबित फाइलों की स्थिति को सीधे निगरानी में रखा जा सकेगा, जिससे फाइलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा।नई प्रणाली से विभागीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और दक्ष हो जाएंगी। अब तक की पुरानी प्रणाली में फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी, और फाइलों का त्वरित निपटान संभव होगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और सुशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही, यह प्रणाली भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी और सरकारी कामकाज में तकनीकी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मंत्री चौधरी ने इस नई प्रणाली के तहत जीएसटी विभाग का कामकाज ऑनलाइन निपटाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने एक फाइल को ऑनलाइन मंजूरी प्रदान की, जो ई-ऑफिस प्रणाली के शुरू होने के बाद उनके द्वारा निराकृत की गई पहली फाइल है। (जगत फीचर्स)

छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत ट्रेन, दुर्ग से विशाखापट्नम अब नो टेंशन

-संवाददाता

जगत प्रवाह. दुर्ग। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हो गई थी लेकिन किसी कारणवश तब इस ट्रेन को पटरी पर नहीं लाया जा सका। अब एक बार फिर नए सिरे से रेलवे ने कवायद तेज कर दी है। यह ट्रेन दुर्ग से रायपुर, खरियार रोड, टिटिलागढ़ और विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम पहुंचेगी। रायपुर रेल मंडल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे बोर्ड से नोटिफिकेशन आते ही ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत का परिचालन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक देश भर में 10 अलग-अलग स्थानों से वंदे भारत चलेगी। उसमें एक छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है. दुर्ग से शुरू होने वाली इस नई वंदे भारत ट्रेन का छत्तीसगढ़ में रायपुर, महासमुंद, ओडिशा में खरियार रोड, टिटिलागढ़, रायगढ़ा और आंध्रप्रदेश के विजयनगरम में स्टॉपेज होगा।

कितने बजे का हो सकता है शेड्यूल?

: ये ट्रेन दुर्ग से सुबह 6 बजे चलेगी और 565 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर 2:30 बजे के करीब विशाखापट्टनम पहुंचेगी। वहां से दोपहर करीब 3 बजकर 15 बजे चलेगी और रात 11 बजकर 50 मिनट पर दुर्ग लौटेगी। नई वंदे भारत ट्रेन की साफ सफाई और रखरखाव दुर्ग रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड में होगा। यहां पर वंदे भारत ट्रेन की रैक के अनुरूप एक पिट लाइन में आवश्यक फेरबदल कर व्यवस्था बना ली गई है.टिटलागढ़ में स्टाफ होगा चेंज :इस ट्रेन को दुर्ग के लोको पायलट सहित अन्य रनिंग स्टाफ टिटिलागढ़ तक लेकर जाएंगे.आगे विशाखापट्टनम तक ट्रेन लेकर जाने की जवाबदेही टिटिलागढ़ का रनिंग स्टाफ संभालेगा। विशाखापट्टनम से वापसी के समय टिटिलागढ़ से फिर एक बार दुर्ग का स्टाफ ट्रेन को लेकर पहुंचेगा। इस ट्रेन के लिए चिन्हित पायलट और असिस्टेंट पायलट की ट्रेनिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। (जगत फीचर्स)

नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर ने की पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय डिप्टी कलेक्टर महेन्द्र पटेल को अब आपने कार्य के साथ साथ नजूल अधिकारी का कार्य सौंपा है। पहले यह प्रभारी नरसिंहपुर एसडीएम मणींद्र सिंह के पास था। इसके अलावा तेंदूखेड़ा के प्रभारी तहसीलदार नीरज को तहसीलदार गोटेगाँव नायाब तहसीलदार श्रीमती नीलम श्रीवास को चीचली तहसील गाड़रवारा, नायाब तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत को प्रभारी तहसीलदार तेंदूखेड़ा, नायाब तहसीलदार अनु जैन को बोहानी तहसील गाड़रवारा, नायाब तहसीलदार रमाकांत चौकसे को तहसील गोटेगाँव और नायाब तहसीलदार महेश बट्टी को तहसील गाड़रवारा पर नियुक्त किया गया है। सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थित दें और इसका प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। (जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

पिता-पुत्र के बीच हुए आत्मीय संवाद की यादें ही बस रह गईं

सिर से पिता का साया उठ जाना जीवन की अपूरणीय क्षति है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस समय अपने पिता श्री पूनम चंद जी यादव को खोने के गहन दुःख में हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनमचंद यादव का निधन हो गया। उनकी उम्र करीब 100 साल थी और वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। खबरों के अनुसार पूनमचंद जी को पिछले हफ्ते ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किसी करीबी के दुनिया छोड़ कर चले जाने बाद अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वह सिर्फ उस व्यक्ति की आपसे जुड़ी यादें ही होती हैं। ऐसी कुछ यादें हैं डॉ. मोहन यादव और उनके पिता की, पिता पुत्र के आत्मीय संवाद का एक वीडियो तब चर्चाओं में था, जब मोहन यादव नए नए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।

मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मोहन यादव चर्चाओं में आए तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान पिता-पुत्र के बीच काफी गपशप और हंसी मजाक होती है। मुख्यमंत्री अपने हाथों से पिता को खुद के लाए एक जैकेट पहनाते हैं।

इसी बीच मुख्यमंत्री अपने पिता से कुछ पैसे मांगते हैं, इस पर उनके पिता अपनी अपनी जेब से 5-5 सौ रुपये के नोटों की गड्डी निकाल कर मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथ में थमा देते हैं। बाद में मुख्यमंत्री उसमें से पांच सौ का एक नोट रख लेते हैं और बाकी पैसे पिता को लौटा देते हैं। हालांकि, पिता उनसे पूरी गड्डी लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह पिता के पांव छूकर आशीर्वाद कर निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनमचंद यादव जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है, रतलाम के रहने वाले पूनमचंद जी काम की तलाश में रतलाम से उज्जैन आए थे। पूनमचंद जी ने हीरा मिल में काम किया और अपने परिवार का भरण पोषण किया। पूनमचंद यादव ने मिल में नौकरी करने के बाद उज्जैन शहर में अपनी दुकान खोली थी। उन्होंने उज्जैन के मालीपुरा में भजिया और फ्रीगंज में दाल-बाफले की दुकान खोली थी, उनकी यह दुकान आज भी शहर में चलती है।

सियासी गहमागहमी

कर्मशील और कर्मयोगी हैं मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जब किसी के घर में कोई आकस्मिक विपत्ति आ जाती है तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ उस विपत्ति को दूर करने में परिवार के साथ होता है। ऐसे समय में उस व्यक्ति के लिये उसका परिवार ही सब कुछ होता है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाज में एक नई मिसाल पेश की है। अपने पिता के देहावसन के कुछ ही घंटों बाद राज्य की जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते फोन पर ही अधिकारियों से बैठक की और धार सहित अन्य जिलों में हुई अत्याधिक बारिश सहित अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्य का यह अंदाज उन्हें कर्मशील और कर्मयोगी पुरुष बनाता है। मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया कि उनके कि लिये जितना महत्वपूर्ण अपना परिवार है उतना ही महत्वपूर्ण है राज्य और राज्य की जनता। वे राज्य और इसकी जनता को भी अपना परिवार मानते हैं यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्र प्रथम के मंत्र को आत्मसात करते हुए समाज कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाया।

कमलनाथ को मिल सकती है नई जिम्मेदारी

पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके कमलनाथ को एक बार फिर पार्टी आलाकमान नई जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है। चर्चा इस बात की है कि मध्यप्रदेश में लगातार वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मनमानियों की खबरें पार्टी आलाकमान तक पहुंची है जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में पटवारी पर आलाकमान द्वारा लगातार समझाईश भी दी गई है लेकिन फिलहाल कुछ परिवर्तन होता दिख नहीं रहा है। ऐसे में आलाकमान के सूत्र बता रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों में ही कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर पार्टी विचार कर रही है जिसके परिणाम आना बाकी है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

भाजपा शासित राज्यों में 'कानून और संविधान' की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं, जिनपर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है।

सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा 'Rule Of Law' पर विश्वास ही नहीं करती।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

महाराष्ट्र और पूरा देश जानना चाहता है आखिर प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी क्यों मांगी! 1. बिना merit के RSS वालों को contract देने के लिए
2. मूर्ति के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के लिए
3. या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पूजनीय महापुरुष का अपमान करने के लिए

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

प्रखर वक्ता और कुशल विदेश मंत्री के रूप में विशिष्ट स्थान रखती थीं सुषमा स्वराज

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन उनकी यादें हमेशा हमें उनकी स्मृतियों से जोड़े रखती हैं। फिर चाहे वह राजनीति के मंच से जुड़ी हो या फिर एक प्रखर विपक्षी नेता के स्वरूप की। बतौर विदेश मंत्री उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 14 फ़रवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में जन्मी सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। अम्बाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद सुषमा ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से क़ानून की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में सुषमा ने लगातार तीन वर्षों तक एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और हरियाणा सरकार के भाषा विभाग की आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगातार तीन बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार जीता।

क़ानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में सुषमा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठन पर सुषमा बीजेपी में शामिल हो गयीं। वह अंबाला से दोबारा विधायक चुनी गयीं और बीजेपी-लोकदल सरकार में शिक्षा मंत्री बनाई गयीं। 1990 में सुषमा राज्यसभा की सदस्य बनीं। छह साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतीं और अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गयीं। इसी दौरान उन्होंने लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का फ़ैसला किया था।

1998 में सुषमा दोबारा दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं। इस बार उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ ही दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय फ़िल्म को एक उद्योग के रूप में घोषित करना रहा। इस फ़ैसले के बाद भारतीय फ़िल्म उद्योग को बैंकों से क़र्ज़ मिल सकता था। अक्तूबर में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया और बतौर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला। हालांकि दिसंबर 1998 में उन्होंने राज्य विधानसभा सीट से इस्तीफ़ा देते हुए राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की और 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ चुनाव मैदान में उतरीं लेकिन वो हार गयीं। फिर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में संसद में वापस लौट आयी।

वाजपेयी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो फिर से सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गयीं। बाद में उन्हें स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2009 में जब सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा पहुंची तो अपने राजनीतिक गुरु लालकृष्ण आडवाणी की जगह 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाई गयीं। 2014 तक वो इसी पद पर आसीन रहीं। 2014 में वो दोबारा विदिशा से जीतीं और मोदी मंत्रिमंडल में भारती की पहली पूर्णकालिक विदेश मंत्री बनाई गयीं। प्रखर और ओजस्वी वक्ता, प्रभावी पार्लियामेंटेरियन और कुशल प्रशासक मानी जाने वाली सुषमा स्वराज एक वक़्त वाजपेयी के बाद सबसे लोकप्रिय वक्ता थीं। सुषमा स्वराज बीजेपी की एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत, दोनों क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। वह भारतीय संसद की ऐसी अकेली महिला नेता हैं जिन्हें असाधारण सांसद चुना गया। वह किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता भी थीं।

जब जंगल कटेंगे तो जानवर रिहायशी इलाकों में आयेंगे

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

जगत प्रवाह. भोपाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज भेड़ियों का आतंक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के हमले की कहानी नई नहीं है। 1996 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में भेड़ियों ने 30 बच्चों को मारा था। जयपुर में पिछले हफ़्ते रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस गया था। जब जानवर अपने घरों से विस्थापित होते हैं, तो वे हमारी बनाई दुनिया में अपनी जगह खोजने के लिए भटकते हैं। हमने उनकी जमीन छीन ली, और अब वे हमारी बनाई हुई दुनिया में जीने के लिए मजबूर हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय शहरों और कस्बों में एक नया दृश्य सामने आया है। वन्यजीवों का आवास जंगलों से सिमटता जा रहा है, और परिणामस्वरूप वे मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वह तेंदुओं का शहरी क्षेत्रों में दिखना हो, हाथियों का गाँवों में प्रवेश, या फिर बंदरों का खुले बाजारों में उत्पात मचाना हर ओर वन्यजीवों का अस्तित्व संकट में है। यह समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई है। वन्यजीवों का मानव बस्तियों की ओर आना कोई नई घटना नहीं है। आदिकाल से मानव और प्रकृति के बीच एक सह-अस्तित्व का रिश्ता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह संतुलन बिगड़ गया है। जहाँ पहले जंगल घने और विशाल थे, आज उनकी जगह कंक्रीट के जंगल ले रहे हैं। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि विस्तार के चलते जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। परिणामस्वरूप, वन्यजीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं और उनके पास अपने जीवन को जारी रखने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा है। इसी कारण वे भोजन और पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। वन्यजीवों का यह विस्थापन सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। जब तेंदुआ या हाथी गाँवों में प्रवेश करता है, तो न केवल उनके द्वारा जान-माल का नुकसान होता है, बल्कि उन जानवरों के लिए भी यह अनुकूल नहीं होता। मनुष्यों द्वारा किया गया हमला और भय का सामना करने के बाद वे और आक्रामक हो जाते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ता है। वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष का एक बड़ा सामाजिक पहलू है। जंगलों के कटने से वनवासियों और ग्रामीणों की जीवनशैली पर गहरा असर पड़ता है। बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों पर ही निर्भर करते हैं। चाहे वह जल, जंगल, जमीन से जुड़ा उनका अधिकार हो या फिर उनकी परंपरागत जीवनशैली। जंगलों की कटाई के चलते न केवल वन्यजीवों का घर छिन रहा है, बल्कि इन समुदायों की आजीविका भी खतरे में आ रही है। जंगलों के विनाश से जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी प्रजातियां, वनस्पति, जीव-जंतु, पक्षी—अपनी प्राकृतिक जगहों पर रहें। जब हम जंगलों को काटते हैं, तो हम उस संतुलन को नष्ट कर देते हैं जो हजारों सालों से प्रकृति ने खुद बनाया है। इसके परिणामस्वरूप, पारिस्थितिकी तंत्र की शृंखला टूट जाती है और प्राकृतिक संसाधनों का चक्र बिगड़ जाता है।

भारत में जंगलों की कटाई की दर चिंताजनक है। वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में हजारों हेक्टेयर जंगलों को नष्ट किया गया है। यह कटाई मुख्यतः औद्योगिकीकरण, कृषि के विस्तार और नगरीकरण के कारण हो रही है। जहाँ पहले घने जंगल हुआ करते थे, वहाँ अब बड़े-बड़े शहर और फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं। सरकार की नीतियाँ भी कई बार इस समस्या को बढ़ावा देती हैं। विकास की आड़ में वन क्षेत्रों को उद्योगों और बस्तियों के लिए खोल दिया जाता है, जिससे वन्य जीवों के पास कोई विकल्प नहीं बचता।

(शेष पेज 6 पर)

राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का महत्व

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

जगत प्रवाह. भोपाल। हमारे समाज के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने का दिन है। यह वही दिन है जब हम न केवल अपने गुरुओं को आदर और धन्यवाद देते हैं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, अनुशासन और मार्गदर्शन के महत्व को भी समझते हैं। शिक्षक वह दीया हैं, जो हर छात्र के जीवन को रोशनी से भरते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। भारत में प्राचीन काल से ही गुरु-शिष्य की परंपरा का बहुत अधिक महत्व रहा है। यहां गुरुओं को हमेशा से विशेष स्थान दिया गया है। यहां तक कि उन्हें भगवान और माता-पिता से भी ऊपर माना गया है। ऐसे में शिक्षक दिवस भारत देश में कोई आम दिन नहीं रह जाता। देश भर में शिक्षकों और गुरुओं के प्रति अगाध आस्था है, जिसके चलते उनको बहुत सम्मान दिया जाता है और शिक्षक दिवस भारत देश में विशेष महत्व का दिन बन जाता है। यही वजह है कि शिक्षक दिवस पर भारत के हर छोटे-बड़े स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज आदि के छात्र इस दिन को विशेष बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी अपने गुरुओं, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों को याद करते हैं। शिक्षा ही हमारे समाज के उत्थान की कुंजी है और शिक्षक ही इस कुंजी के धारक होते हैं। हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्त्व को रेखांकित करने के लिए शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे हमें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं, जो हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक दिवस का महत्व यह भी है कि यह हमें याद दिलाता है कि शिक्षा हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षकों के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता और इसलिए हमें उनके प्रति गहरा समर्पण और आभार दिखाना चाहिए। वे न केवल हमें पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण भी करते हैं और इस दिन के माध्यम से हम उनके योगदान के लिए सराहना करते हैं। (जगत फीचर्स)

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित हुआ दुष्कर्मियों को फांसी की सजा का कानून

-प्रमोद भार्गव

देश में अनेक कानूनी उपाय और जागरूकता अभियानों के बावजूद बच्चों एवं महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में घटित निर्भया, हैदराबाद की महिला पशु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी और अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामलों से यही प्रकट हुआ है कि जब सरकार और पुलिस कानून व्यवस्था के अमल में लाचारी का सामना करती है तो एक नए कथित कठोर कानून 'अपराजिता महिला-बाल सुरक्षा विधेयक' लाकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। 2012 में घटित निर्भया कांड में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कठोर कानून लायी थी। इसे त्वरित न्याय का पर्याय भी माना गया था, लेकिन जब फांसी की सजा हुई तो उसे देने का कानूनी क्रिया-कर्म करने में पूरे आठ साल लग गए थे। हैदराबाद के मामले में तो पुलिस ने दुष्कर्म के चार आरोपियों को छह दिसंबर 2019 को घटना स्थल पर ले जाकर मुठभेड़ में मार गिरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृत जज बीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले आयोग ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया था। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुष्कर्म पर सरकार, कालेज और पुलिस प्रशासन की कमियों और गड़बड़ियों पर पर्दा डालने के लिए फांसी का कानून ले आईं। आनन-फानन में विधानसभा से पारित इस विधेयक में कहा गया है कि यदि दुष्कर्म के किसी मामले में पीड़िता की मौत हो जाती है, या फिर वह कोमा में चली जाती है तो अपराधी को फांसी दी जाएगी। इस कानून को लाने से पहले यह भी कहा गया था कि 10 दिन के भीतर दोषी को फांसी दे दी जाएगी। परंतु सामने आए कानून में इस समय सीमा का उल्लेख नहीं है। दरअसल समूची भारतीय न्याय व्यवस्था गढ़े गए ऐसे विकल्प और प्रतिविकल्पों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है कि तय समय सीमा में न्याय संभव ही नहीं है।

देश में दुष्कर्म के सर्वाधिक मामलों के परिप्रेक्ष्य में अब्बल रहने वाला मध्य प्रदेश दुष्कर्म पीड़िताओं को त्वरित न्याय और फांसी की सजा का प्रावधान बहुत पहले कर चुका है। मध्य प्रदेश में ऐसा इसलिए संभव हो पाया था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय की दृष्टि से सामूहिक दायित्व निर्वहन की भावना से काम लिया था। चौहान ने ही 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया था। बाद में इस कानून को अन्य राज्यों ने भी अपनाया और अब तो केंद्र सरकार ने भी नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म व हत्या के अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है। बावजूद निचली अदालतों से सजा मिलने के बाद भी ऐसे मामलों में फांसी देने में विलंब हो रहा है।

दुष्कर्म बनाम कानून दर कानून

दुष्कर्म मामलों में त्वरित न्याय का सिलसिला चल निकलने के बाद भी महिलाओं व बालिकाओं से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। एक अध्यादेश लाकर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा और 16 साल से कम उम्र की किशोरी के साथ बलात्कार एवं हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया था। इस अध्यादेश ने कानूनी रूप भी ले लिया है। पॉक्सो कानून की धारा 9 के तहत किए गए प्रावधानों में शामिल हैं कि बच्चों को सेक्स के लिए परिपक्व बनाने के उद्देश्य से उन्हें यदि हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ दिया जाता है तो इस पदार्थ को देने वाले और उसका भंडारण करने वाले भी अपराध के दायरे में आएंगे। इसी तरह पोर्न सामग्री उपलब्ध कराने वाले को भी दोषी माना गया है। ऐसी सामग्री को न्यायालय में सबूत के रूप में भी पेष किया जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि अधिकतम मामलों में पुलिस ने कामवर्धक दवा और अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की दरअसल इस तरह की चीजें बच्चों से बाल्यावस्था छीनने का कारण बनते हैं। किशोर और युवा इनसे प्रेरित होकर किसी स्त्री के साथ अनर्थ कर डालते है। साफ है, यह सामग्री लोगों के शरीर ही नहीं आत्मा को भी छलनी कर रही है।

हालांकि पहले कानून से कहीं ज्यादा आदमी को धर्म और समाज का भय था। नैतिक मान-मर्यादाएं कायम थीं। किंतु इन्हें तार-तार करने का काम कुछ ऐसे कानूनों ने भी किया है, जिनके चलते रिश्तों की गरिमा लगभग खत्म हो गई है। नैतिक पतन के कई स्वरूप होते हैं, व्यक्तिगत, संस्थागत और सामूहिक। व्यक्तिगत पतन स्वविवेक और पारिवारिक सलाह से रोका जा सकता है। किंतु संस्थागत और सामूहिक चरित्रहीनता के कारोबार को सरकार और पुलिस ही नियंत्रित कर सकती है। दवा कंपनियां कामोत्तेजना बढ़ाने के जो रसायन और सॉफ्टवेयर कंपनियां पोर्न फिल्में बनाकर जिस तरह से इंटरनेट पर परोस रही हैं, उस पर काबू कानूनी उपायों से ही संभव है। पोर्न फिल्मों की ही देन है कि जैसे गली-गली में दुश्कर्मी घूम रहे हैं। समाजषास्त्री मानते हैं कि जहां कानूनी प्रावधानों के साथ सामाजिक दबाव भी होता है, वहां बलात्कार जैसी दुश्प्रवृत्तियां कम पनपती है। विडंबना है कि राजनीति का सरोकार समाज-सुधार से दूर हो गया है। उसकी कोशिश सिर्फ सत्ता में बने रहकर केवल उसका दोहन करना भर रह गया है। यही वजह है कि भिन्न विचारधाराओं की राजनीति सत्ता के लिए जिस तरह एकमत हो जाते हैं, उसी तर्ज पर इस दुष्कर्म मामले में भी भिन्न धर्मों के लोग एक हो गए।

स्त्री उत्पीड़न की ज्यादातर घटनां महानागरों के उन इलाकों में घट रही है, जहां समाज और परिवार से दूर वंचित समाज रह रहा है। ये लोग अकेले गांव में रह रहे परिवार की आजीविका चलाने के लिए शहर मजदूरी करने आते हैं। ऐसे मोबाइल पर उपलब्ध कामोत्तेजक सामग्री इन्हें भड़काने का काम करती है और ये चलती-फिरती बालिकाओं अथवा महिलाओं को बहला-फुसलाकर या उनकी लाचारी का लाभ उठाकर यौन उत्पीड़न कर डालते हैं। हैदराबाद की चिकित्सक के साथ घटी घटना की पृष्ठभूमि में लाचारी रही है। इनकी स्कूटी कम आबादी वाले इलाके में पंचर हो गई और इंसानियत के दुष्मन मदद के बहाने हैवानियत पर उतर आए। लाचार ने पालतू मवेशियों के इलाज की पढ़ाई तो की थी, लेकिन इंसानियत के भीतर निवास करने वाले जानवरों के न तो वह लक्षण जानती थी और न ही उनका उपचार करना जानती थी। इस घटना की पृश्ठभूमि में फैलता घहरीकरण और परिचितों से बढ़ती दूरियां भी रही हैं। यही वजह रही कि जिन दरिंदों की मति और मानवीयता जब मर रहे थे, तब उन्हें रोकने के लिए न तो कोई निकट मनुश्य था और न ही दरिंदों को ललकारने वाली कोई आवाज उठी? जबकि रात बहुत गहरी नहीं हुई थी, केवल 9 बजे थे। लेकिन पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों के सायरन भी इस वक्त मौन थे। कोलकाता की चीखें तो उसी अस्पताल में दब गईं, जिसमें वह प्रशिक्षण ले रही थी।

अकसर निर्भया या प्रियंका की चीखें जब मौन होकर राख में बदल जाती है तब देश में हर कोने से मोमबत्ती की टिमटिमाती ज्योति में दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग उठने लगती है। किंतु न्याय शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि जीवन खत्म करने का अधिकार आसान नहीं होना चाहिए। इसलिए फांसी की सजा जघन्यतम या दुर्लभ मामलों में ही देने की परंपरा है। नतीजतन निचली अदालत से सुनाई गई फांसी की सजा पर अमल भी जल्दी नहीं होता। मप्र में 2018 में रिकॉर्ड 58 दोषियों को दुष्कर्म व हत्या के मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन एक भी सजा पर अमल नहीं हो पाया है। यह मामले उच्च, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति के पास दया याचिका के बहाने लंबित हैं। सभी जगह दोशी को क्षमा अथवा सजा कम करने की प्रार्थना से जुड़े आवेदन लगे हुए हैं। इन आवेदनों के निरस्ती के बाद ही दोशी का फांसी के फंदे तक पहुंचना मुमकिन हो पाता है। साफ है, ममता बनर्जी ने मध्यप्रदेश की तरह दुश्कर्म के मामले में कानून कठोर जरूर बना दिया है, लेकिन सजा देने की जो कानूनी संहिता के रूप में दर्ज परतें हैं, वे त्वरत सजा देने में बड़ी बाधा हैं। दुश्कर्म से जुड़े कानूनों को कठोर बना दिए जाने के बावजूद इस परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। पुलिस और अदालतों की कार्य-संस्कृति यथावत है। मामले तारीख दर तारीख आगे बढ़ते रहते हैं। कभी गवाह अदालत में पेष नहीं होते है तो कभी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आने के कारण तारीख बढ़ती रहती है। गोया, इस बाबत न्यायिक व पुलिस कानून में सुधार की बात अर्से से उठ रही है, लेकिन हमारी सरकारों की प्राथमिकता में कानूनी सुधार की चिंता है ही नहीं ? लिहाजा विशेष अदालतें गठित होने के भी सार्थक परिणाम नहीं आए हैं।

(जगत फीचर्स)

जब जंगल कटेंगे तो जानवर रिहायशी इलाकों में आयेंग

(पेज 5 का शेष)

जब जंगल कटते हैं, तो जानवरों के पास न तो भोजन होता है और न ही पानी। जंगलों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण वे इंसानी बस्तियों की ओर जाने को मजबूर हो जाते हैं। तेंदुओं का गांवों में आकर मवेशियों का शिकार करना, हाथियों का खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट करना, और यहाँ तक कि कुत्तों और बंदरों का शहरी इलाकों में आकर भोजन की तलाश करना, यह सभी संकेत हैं कि हमने उनके प्राकृतिक आवासों को छीन लिया है। शहरी क्षेत्रों में यह टकराव न केवल जानवरों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ तेंदुओं के हमलों में लोग घायल हुए हैं, और कई बार इन संघर्षों में वन्यजीवों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। यह घटनाएँ हमें यह बताती हैं कि यह संघर्ष न केवल बढ़ रहा है, बल्कि इसके समाधान की आवश्यकता भी अब पहले से अधिक है।

जंगलों की कटाई का एक अन्य गंभीर परिणाम जलवायु परिवर्तन है। पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमारी वायु शुद्ध होती है। जब हम जंगलों को काटते हैं, तो हम इस प्राकृतिक प्रणाली को कमजोर कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। इसके अलावा, जंगलों की कटाई से बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, जिससे बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ अधिक होने लगी हैं।

अब सवाल यह उठता है कि इस संकट का समाधान क्या हो सकता है? समाधान कई स्तरों पर संभव है। सरकारी नीतियों से लेकर जन जागरूकता तक। सबसे पहले, हमें यह समझना होगा कि जंगलों का संरक्षण केवल वन्यजीवों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। अगर हम जंगलों को नष्ट करते रहे, तो आने वाले समय में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को जंगलों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। औद्योगिक और शहरी विकास की योजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वनों की सुरक्षा और पुनर्वनीकरण (reforestation) की योजनाओं को अधिक महत्व देना होगा। इसके अलावा, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को विस्तार देने की आवश्यकता है ताकि जानवरों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सके।

सामाजिक स्तर पर, हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। वन्यजीवों को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानने के बजाय, हमें उन्हें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा समझना होगा। जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि जंगल और वन्यजीव हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्राचीन काल से ही मानव और वन्यजीवों के बीच एक संतुलित सह-अस्तित्व रहा है। यह सह-अस्तित्व आज भी संभव है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी नीतियों और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अगर हम जंगलों की कटाई रोकने में सफल होते हैं, तो वन्यजीवों को अपने प्राकृतिक आवास में बने रहने का अवसर मिलेगा, और मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष कम होगा।

यह सही समय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और संतुलित भविष्य की नींव रखें। यदि हम आज कदम नहीं उठाते, तो जंगलों और वन्यजीवों का यह संकट न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व पर भी प्रश्नचिह्न लगाएगा। जंगलों का संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा अब केवल वन विभाग का काम नहीं रह गया है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन गई है। समाधान की दिशा में पहला कदम यही होगा कि हम जंगलों को नष्ट होने से बचाएँ और वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी आवास सुनिश्चित करें।

कलम के सिपाही...

अम्बादत्त भारतीय: अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया

-संवाददाता

मध्यप्रदेश के पत्रकारिता जगत में स्व. अम्बादत्त भारतीय का नाम एक जाज्वल्य नक्षत्र के रूप में सदैव दैदीप्यमान रहेगा। सन 1968 के आसपास पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले श्री भारतीय की प्रारम्भिक कर्म स्थली सीहोर जिले में रही। इसके बाद उन्होंने भोपाल में भी पत्रकारिता की। उनके पिता स्व. दुर्गादत्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक और अपने समय के प्रखर पत्रकार थे। दैनिक जागरण, समाचार भारती, पीटीआई, अमृत सन्देश, देशबन्धु, जनधर्म, पहले-पहल आदि प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में उनकी लेखनी ने धूम मचाई थी। इसके अलावा उन्होंने सीहोर न्यूज नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्व. श्री भारतीय का जन्म 22 मार्च 1950 में उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में हुआ था। लगभग दस वर्ष की आयु में परिस्थिति वश वह अपने पिता तथा माता शारदा देवी और छोटे भाई गुरुदत्त भारतीय के साथ सीहोर आ गए। तब से लेकर अपने जीवन के अन्तिम दिनों के दौरान उन्होंने इस शहर को कभी नहीं छोड़ा। उन्हें हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का गहन ज्ञान था। भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक डिग्री लेने वाले वे सीहोर जिले के पहले पत्रकार थे। चार विषयों में एम.ए., बीएड, एल.एल.बी. के अलावा अन्य कई डिप्लोमा कोर्स भी उन्होंने किए। पत्रकारिता के साथ उनकी अध्ययन यात्रा सदैव चलती रहती थी।

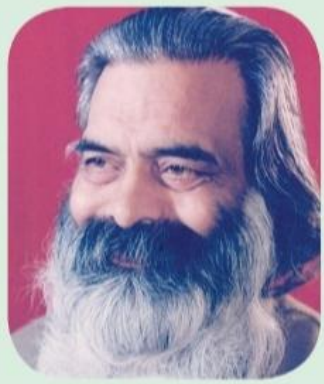

कई स्थानीय और भोपाल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं में उनके समाचार और लेख रजन अथवा रजन भारतीय के नाम से भी प्रकाशित होते रहते थे। सीहोर का हर छोटा-बड़ा शख्स उन्हें सम्मान और आदर से गुरु अथवा बाबा के नाम से ही सम्बोधित करता था। अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी भी उन्हें बाबा ही कहते थे। पत्रकारिता के साथ-साथ स्व. भारतीय जी प्रदेशभर के पत्रकारों को संगठित करने में भी आजीवन लगे रहे। जिला प्रेस क्लब, आंचलिक पत्रकार संघ, इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ आदि संगठनों के माध्यम से नगरीय और आंचलिक पत्रकारों को दक्ष करने को लेकर भी बड़ी चिन्ता लगी रहती थी। यही कारण है कि नगर सहित जिले भर में आपने पत्रकार प्रशिक्षण और कार्यशाला शिविरों के आयोजन कराए। सीहोर जिले में अधिकतर युवा पत्रकार उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते हैं। देश और प्रदेश के अनेक मूर्धन्य पत्रकारों को इस नगर में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से लाने का श्रेय भारतीय जी को ही जाता है।

चम्बल की डकैत समस्या को लेकर लिखी गई उनकी एक पुस्तक चम्बल और माधोसिंह काफी चर्चा में रही। सुकवि स्व. जनार्दन शर्मा तथा सूफी कवि मुल्कराज त्यागी के काव्य संकलन भी उनके सम्पादन में प्रकाशित हुए। स्वराज संस्थान भोपाल से प्राप्त फैलाशिप के साथ आपने कुँअर चैनसिंह तथा सीहोर के विद्रोह को लेकर भी शोध पत्र तैयार किया था।

स्व. अम्बादत्त भारतीय अशिक्षा को लेकर हमेशा चिन्तित रहते थे। इसके चलते आपने सीहोर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़कर सार्थक मुहिम चलाई। उनकी इस उपलब्धि के कारण बिहार के पटना शहर में एक स्वैच्छिक संगठन महेन्द्र सिंह ट्रस्ट ने उन्हें स्वर्ण मुकुट और प्रशस्ति पत्र तथा एक लाख रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया था। उनके साथ देश के प्रख्यात कवि नीरज भी सम्मानित हुये थे। उन्होंने जिले भर के अधिकांश गाँवों में साक्षरता का अलख जगाने के लिए अनेक नुक्कड़ नाटकों का मंचन भी किया और स्वयं भी भूमिका निभाई।

स्व. डॉ. शंकर दयाल शर्मा, केन्द्रीय मंत्री रहे भगवत झा आजाद, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मुख्यमंत्री वोरा, मंत्री रहे स्व. भैया उमराव सिंह, उत्तराखण्ड के राज्यपाल अजीज कुरैशी, पूर्व संसदीय सचिव अजीत सिंह आदि से उनके पारिवारिक सम्बन्ध थे। स्व. उमराव सिंह जी को वह अपने पिता तुल्य मानते थे। श्री भारतीय में फोन पर समाचार नोट कराने की अद्भुत कला थी।

स्व. अम्बादत्त भारतीय जी सीहोर जिले के प्रथम ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित कर दिया। उनका समर्पण इतना अधिक था कि पत्रकारिता के चलते उन्होंने अपना विवाह भी नहीं किया। उनका मानना था कि यह क्षेत्र ऐसा है जहाँ ईमानदारी से पत्रकारिता की जाए तो जोखिम ही जोखिम है। इसलिए किसी तरह का बन्धन नहीं होना चाहिए। वे यह भी कहा करते थे कि जिस तरह से देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसी प्रकार देश के विकास और निर्माण में भी उसी भावना के साथ पत्रकारों का योगदान होना चाहिए। यह संस्कार उन्हें विरासत में अपने पिता जी से मिले थे। हालाँकि अपने यह विचार उन्होंने कभी भी अपने किसी पत्रकार साथी पर नहीं थोपे। स्व. अम्बादत्त भारतीय सिद्धान्त के इतने पक्के थे कि उन्होंने कई मौकों पर आर्थिक, राजनैतिक और अन्य तरह के प्रलोभनों को ठुकरा दिया। एक राजनैतिक दल की ओर से एक बड़े नेता के माध्यम से उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी मिला था, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। स्व. अम्बादत्त भारतीय को ज्योतिष शास्त्र में भी गहरी रुचि थी। हालाँकि इस विधा को उन्होंने कभी भी व्यावसायिक नहीं बनाया। अंक विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, हस्त रेखा विज्ञान और जन्म कुण्डली का गहन अध्ययन था। जिला चिकित्सालय के प्रायवेट वार्ड का कमरा नम्बर तीन जहाँ हाथ में स्लाइन लगी हुई स्थिति में लेटे बाबा भारतीय जिनका कृषकाय शरीर तो था, लेकिन आवाज में वही चिर परिचित बुलन्दी थी। भारत जोड़ो आन्दोलन द्वारा आयोजित कुँअर चैनसिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में देश के वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वेदप्रताप वैदिक के हाथों उनका सम्मान पत्र मैंने ग्रहण किया था। 25 जुलाई को मैंने उन्हें वह सम्मान पत्र अस्पताल में जाकर दिया था।

आखिर कब बंद होगा भ्रष्टाचार का यह नया तंत्र (पेज 1 का शेष)

और मालूम चला कि यह सब वहीं बाबू महाशय है जो अपने कार्यकाल के दौरान लंबे भ्रष्टाचार के लिये जाने जाते थे और उच्चाधिकारियों तक मोटी रकम पहुंचाने की तरकीब जानते थे। अब देखने वाली बात यह है कि यह अपनी आंखों के सामने होते हुए भी मुख्यमंत्री यादव कोई कदम उठाते हैं या फिर यह सब इसी तरह से चलता रहेगा।

संस्कृति और पर्यटन में भी खूब चल रही है बाबूओं की

मध्यप्रदेश का संस्कृति और पर्यटन विभाग भी रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों की मोहमाया से वंचित नहीं रह पाया है। यहां भी एक नहीं कई अधिकारियों को उच्चाधिकारियों ने मंत्री की मंशा के बगैर अपने बल पर दोबारा से मोटी तनख्वाह पर रख लिया है। फिर बात चाहे संस्कृति विभाग में पदस्थ हरिचंदन भट्टी की हो या फिर मप्र पर्यटन बोर्ड में पदस्थ युवराज पडोले की। दोनों ही ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनके ऊपर सेवाकाल के दौरान एक नहीं कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगें लेकिन विभाग के उच्चाधिकारियों ने इनको लेकर हुई प्रत्येक शिकायतों पर पर्दा डाल रखा और रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद दोबारा इन्हें कुर्सी पर बुला लिया है। चर्चा इस बात की भी है कि पर्यटन बोर्ड तो पूरी तरह से डेप्युटेशन और रिटायर्ड कर्मचारियों के बल पर चल रहा है। ऐसे में अगर बोर्ड का संचालन किया ही जाना है तो योग्य युवाओं को मौका देना चाहिए न कि भ्रष्ट रिटायर्ड अधिकारियों को।

मुख्यमंत्री कई बार दे चुके हैं चेतावनी पर सुनता कौन है

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक बार नहीं कई बार अधिकारियों को यह निर्देश दे चुके हैं कि सेवानिवृत्ति के पहले संबंधित अधिकारी के जांच पूरी तरह से कर लें अगर कोई कमी या गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कार्यवाही तुरंत की जाये लेकिन मुख्यमंत्री की बात को सुनने वाले इस प्रदेश में आईएएस अफसर बचे ही नहीं हैं। पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि शासकीय सेवा में रहते आर्थिक गड़बड़ी या पद के दुरुपयोग की शिकायतों पर चलने वाली विभागीय जांच अब सेवानिवृत्ति के पहले पूरी करनी होगी। इसके लिए प्रक्रिया तय करने वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जो एक सप्ताह में मुख्य सचिव वीरा राणा को रिपोर्ट देगी।

ऐसे आया था मामला सामने

दरअसल, हर कैबिनेट बैठक में पांच-सात प्रकरण अधिकारियों-कर्मचारियों की विभागीय जांच पर निर्णय के लिए आते हैं। कमल नाथ सरकार में ऐसे प्रकरणों को कैबिनेट में लाने के स्थान पर निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बना दी थी लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह व्यवस्था बंद हो गई और फिर कैबिनेट में प्रकरण भेजे जाने लगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब यह पता होता कि जिसकी जांच चल रही है, वह कब सेवानिवृत्त हो रहा है तो फिर प्रकरण का निराकरण सेवा में रहते ही हो जाना चाहिए। यदि वह दोषी है तो सेवा में रहते ही वसूली आदि की कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। कर्मचारी को भी बार-बार दूरदराज से आना नहीं पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लिये गये ऐतिहासिक फैसले से महिलाओं के जीवन में आया बदलाव

(पेज 1 का शेष)

इसके साथ ही सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले पारिश्रमिक को भी 4000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा करने का फैसला किया है।

बदलाव सहित लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने, तेंदू पत्ता संग्राहकों का परिश्रमिक बढ़ाने, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम में बदलाव समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

महिलाओं को मिल रहे 1000 रुपये प्रतिमाह

छत्तीसगढ़ सरकार ने 'मोदी की गारंटी' के तहत घोषणा पत्र में शामिल एक और योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह यानी कि हर साल 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। महिलाओं के साथ हुए लिंग भेद, असमानता और जागरूकता की कमी के चलते समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है. इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों का बढ़ाया गया पारिश्रमिक

बैठक में सरकार ने राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए उनका पारिश्रमिक 4000 रुपये प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का फैसला लिया है। इस योजना के लिए धनराशि का 75 प्रतिशत सरकार देगी, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के पिछले नियमों को फिर से लागू करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने अगस्त 2023 में अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन किया था, जिसे एक बार फिर बदलते हुए सरकार ने पुराने नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही विष्णुदेव कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया है. जिसके बाद भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा।

विवाहित महिलाओं के सीधे बैंक खाते में जाएगा पैसा

कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने पीएम नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात् साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, उन्हें मिलेगा। इतना ही नहीं विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।

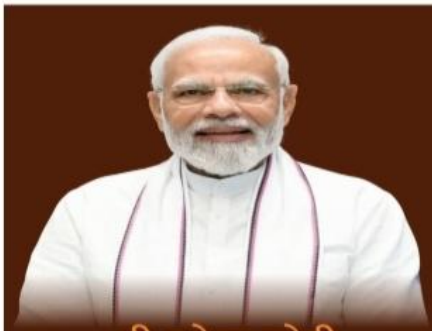

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

विष्णु के सुशासन से
सँवर रहा छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन से विकास की नई राह...

- कृषक उन्नति योजना : धान का प्रति क्विंटल 3100 रुपए मिल रहा दाम, खेती-किसानी से खुले समृद्धि के द्वार
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 47 हजार 90 आवासहीन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा लाभ

- शासकीय भर्ती में आयु सीमा में छूट: पुलिस विभाग सहित शासकीय भर्तियों में युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
- भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित

- मुफ्त अनाज: छत्तीसगढ़ के 68 लाख गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक निःशुल्क राशन
- तेंदूपत्ता संग्राहक पारिश्रमिक: 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा

- 'नियद नेल्लानार' अभियान के साथ नक्सल समस्या के पूर्ण निदान के प्रभावी कदम
- त्वरित निर्णय, सरल प्रशासन: विष्णु देव सरकार में अब तक 150 माओवादी मुठभेड़ में ढेर, 599 की गिरफ्तारी, 510 ने किया आत्मसमर्पण

RO No. 12929/1

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें...

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे

Visit us : ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)